as a national project; if so, what are the details thereof; and at what stage the consideration is pending?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): The Polavaram Project which envisages ultimate potential of more than one lakh hectares and also having inter-state aspects fulfil the criteria evolved by Central Water Commission for its inclusion as one of the projects of national importance. The Ministry's proposals to take up the scheme for providing special central assistance to national projects for expeditious completion during the VIII Plan has not been accepted by the Planning Commission.

राज्यों में सिंचाई दर

1599. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में सिंचाई की दर भिन्न-भिन्न हैं;

(ख) सिंचाई दरों में समानता लाने के लिये सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये हैं; और

(ग) उनका क्या परिणाम निकला है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों द्वारा जल दरें वसूल की जाती हैं और ये परियोजना-दर-परियोजना तथा फसलों और मौसमों में भिन्न भिन्न होती हैं। सितम्बर, 1987 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा अपनायी गई राष्ट्रीय जल नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई है कि जल दरें ऐसी होनी चाहिए कि प्रयोगकर्ताओं को संसाधन के अभाव का अनुभव हो सके और उन्हें जल के उपयोग में किफायत करने के वास्ते प्रेरित किया जा सके । ये दरें वार्षिक अनुरक्षण तथा संचालन प्रभारों और निश्चित लागतों के एक हिस्से को कवर करने में पर्याप्त होनी चाहिए । सिंचाई जल के सुनिश्चित तथा समय पर आपूर्तियां सुनिश्चित करते समय इसे काफी अवधि तक सर्वांगपूर्ण बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए । सतही जल तथा भूजल की जल दरें लघु तथा सीमान्त कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, युक्तियुक्त बनायी जानी चाहिएं । इसकी वसूलियों और अन्य संबंधित मुद्दों में सुधार करने के लिए मूल्य संरचना तथा रूपात्मकताओं के विद्यमान तंत्र की जांच करने हेतु योजना आयोग ने अक्तूबर, 1991 में सिंचाई जल की लागत पर एक समिति गठित की है । और इसे अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1992 के अन्त तक प्रस्तुत करनी है ।

National Water Development agency

1600. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the National Water Development agency has assessed the possible annual surplus water available from harnessing the major inter-State and international rivers of the country;

(b) if so, what would be the quantum of surplus water and how much hectares of land which can be benefited with that surplus water;

(c) the hectares of land which can be irrigated with the surplus waters of Achankovil basin of Kerala and odavari basin of Andhra Pradesh; and

(d) the steps have been taken by Government to use surplus waters in the drought prone States?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b) In the National perspective additional water that can be utilised through inter-basin transfer was estimated as 22 million hectare-metres to benefit 35 million hectares of land. The studies undertaken by National Water